- भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है
   ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम (1773-1858) तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम (1858-1947)
- रेग्युलेटिंग एक्ट पारित 1773 ई. में
- बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद दिया गया -रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा
- बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना
   वारेन हेस्टिंगस
- कलकता (बंगाल) में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई - 1774 ई. में, रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के तहत
- कलकता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे - सर एलिजाह इम्पे
- बिहार, बंगाल और उिंह्सा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया- 1781 ई. के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत
- कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया - 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
- कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु 'बोर्ड
  ऑफ कंट्रोलर' और व्यापारिक कार्यों के लिए
  'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' का प्रारंभ हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा
- गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापित नियुक्त किया
   गया संशोधन अधिनियम, 1786 द्वारा
- 1786 अधिनियम का संबंध कार्नवालिस से
- कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा
   दिया गया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा
- बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया - 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा
- पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1
   लाख रूपये खर्च करने का उपबंध किया गया
   1813 के चार्टर एक्ट द्वारा
- ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त - 1813 के एक्ट द्वारा
- इंगलिश मिशनिरयों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई - 1813 के एक्ट द्वारा
- बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया - 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
- भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना
   लॉर्ड विलियम बैंटिक
- भारतीय प्रशासन का केन्द्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया - 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
- भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया - 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
- प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया - लॉर्ड मैकाले (इंगलैंड के वकील)
- मारत में दास प्रथा को समाप्त किया 1843 में एलनबरो ने, चार्टर एक्ट 1833 के तहत
- भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर

## संवैधानिक विकास

नियुक्ति का प्रावधान किया गया - चार्टर एक्ट 1833 में

- भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई - चार्टर एक्ट 1853 के तहत
- भारत में सिविल सेविकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया
   चार्टर एक्ट 1853 के तहत
- भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय
   दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई - 1853 एक्ट द्वारा
- भारतीय (केन्द्रीय) विधान परिषद् की स्थापना की गई - 1853 एक्ट द्वारा
- भारत का शासन 'कंपनी' से लेकर ब्रिटिश
   'क्राउन' के हाथों में सौंपा गया भारत
   शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा
- गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर 'वायसराय' कर दिया गया - भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा
- भारत के प्रथम वायसराय तथा ॲतिम गवर्नर जनरल हुए - लॉर्ड कैनिंग
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर 'भारत के राज्य सचिव' पद का सृजन किया गया - भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा
- महारानी विकटोरिया को भारत की सम्राज्ञी
   घोषित किया गया 1858 ई. में
- कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरूआत हुई - भारत परिषद् अधिनियम, 1861 के द्वारा
- वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई - भारत परिषद् अधिनियम, 1861 के द्वारा
- भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत की गई
   भारत परिषद् अधिनियम, 1892 द्वारा
- भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई - भारत परिषद्
   अधिनियम, 1892 द्वारा
- मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है
   भारत परिषद् अधिनियम, 1909 को
- मार्ले-मिन्टो सुधार का उद्देश्य था
   पथक निर्वाचन प्रणाली
- पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया - भारत परिषद् अधिनियम, 1909 के तहत
- सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है - लॉर्ड मिन्टो-॥ (वायसराय) को
- 1909 ई. में इंगलैंड में भारत के राज्य सचिव
   थे लॉर्ड मार्ले
- माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है - 1919 का शासन अधिनियम को

- केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई - 1919 का भारत शासन अधिनियम/माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापात्रा की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा
- प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे
   -िलयोनस कार्टियस
- भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया - 1919 अधिनियम द्वारा
- केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926
   में ली आयोग के सिफारिश पर
- ♦ ली आयोग का गठन 1923-24 में
- भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला - मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत शासन अधिनियम, 1919) द्वारा
- अखिल भारतीय संघ अर्थात् भारत में संघात्मक सरकार (संघीय शासन) की स्थापना की गई
   भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा
- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई - 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा
- वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई - 1935 अधिनियम द्वारा
- देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई -भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा
- भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित 'भारतीय परिषद्' का अंत कर दिया गया – भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा
- बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत 'सिंध' एवं 'उड़ीसा' का निर्माण हुआ – भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत.
- ♦ बर्मा, भारत से अलग हुआ 1937 में
   ♦ प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी
- भारत शासन अधिनियम, 1935 का
- प्रांतीय स्वायत्तता लागू 1 अप्रैल, 1937 को
   अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना
- -भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा

  ♦ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया

  था 18 जुलाई, 1947 को
- ◆ वायसराय का पद समाप्त कर 'गवर्नर-जनरल'
   पद स्जित किया गया भारतीय स्वतंत्रता
   अधिनियम, 1947 द्वारा
- भारत को स्वतंत्र एवं संप्रमु राज्य घोषित किया गया - 15 अगस्त 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा
- भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है – माउण्टबेटन योजना
- भारत के आजादी के समय इंगलैंड में सरकार
   थी लेबर पार्टी की
- भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात् शासन चलाया गया - 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार

## सिंवधान सभा का गठन किया गया था-कैबिनेट मिशन (1946) की सिफारिश पर

- 'संविधान सभा' शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था - हेनरी भैन द्वारा
- संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला
   देश है अमेरिका (1787 में)
- स्रविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया - एम, एन, रॉय द्वारा, 1934 में
- कैबिनेट मिशन भारत आया- 24 मार्च 1946
   को. पैथिक लॉरेंस (अध्यक्ष) के नेतृत्व में
- कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए. वी. अलेक्जेंडर
- कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था - संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन
- कैबिनेट मिशन के तहत सिंविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी - 389 (292 ब्रिटिश प्रांतो से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटें देशी रियासत से)
- चार कमिश्नरी क्षेत्र थे अजमेर-मारवाड़, बलुचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली
- स्विधान सभा में महिलाओं की संख्या 15
- सिंवधान सभा में सीटें आविंटत की गई थी -प्रति दस लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में
- स्विधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था
   प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष
   निर्वाचन के द्वारा
- संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या थी - कमश : 26 तथा 33
- जुलाई, 1946 में सिवधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी - क्रमश: 208 एवं 73
- सोंवधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों
   ने भाग नहीं लिया हैदराबाद
- देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे - 299
- स्वतंत्रता पश्चात् देश में रियासतें थी 562
- संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 में
- अंतरिम सरकार का गठन -2 सितम्बर 1946
   को जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में
- सिंवधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर,
   1946 को दिल्ली में (सदस्य-207, मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था)
- सिवधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
   सिच्चदानंद सिन्हा ने (अस्थायी अध्यक्ष)
- सॅविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे
   वी॰ एन॰ राव
- सिवधान सभा का प्रारूप तैयार किया था
   वी॰ एन॰ राव (बेनेगल नरसिंह राव) ने
- सर्विधान सभा को संबोधित करने वाले पहले
   व्यक्ति थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकणान
- ♣ डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद सर्विधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए- 11 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में

## भारतीय राजव्यवस्था

- संविधान समा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था - उद्देश्य प्रस्ताव
- ⁴ उद्देश्य प्रस्ताव¹ पेश किया गया था जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर, 1946 को
- ♦ उद्देश्य प्रस्ताव को 'उद्देशिका' के रूप में पारित किया गया - 22 जनवरी, 1947 को
- ◆ 'उद्देशिका' को ही कहा गया प्रस्तावना
- ब्रिटिश भारत में सबसे पहले 'प्रस्तावना' का प्रावधान किया गया -1919 के अधिनियम में
- भारतीय 'संविधान की प्रस्तावना' शुरू होती है
   'हम भारत के लोग' से
- प्रस्तावना/उद्देशिका लिया गया अमेरिका से
- प्रस्तावना की भाषा लिया गया- ऑस्ट्रेलिया से
- प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार (42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा)
- संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी, पंथिनरपेक्ष तथा अखंडता' शब्द जोड़ा गया था - 42वाँ संशोधन 1976 द्वारा (इंदिरा गांधी के समय)
- प्रस्तावना को संविधान का भाग/अंग स्वीकार किया गया - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में (1973 में)
- ∳ 'भारतीय संविधान की आत्मा' है प्रस्तावना
- प्रस्तावना को 'भारतीय सर्विधान की आत्मा/कुँजी' कहा है – ठाकर दास भार्गव ने
- बी॰ आर॰ अम्बेडकर ने 'भारतीय सॉवधान की आत्मा' कहा है - अनुच्छेद 32 को (संवैधानिक उपचारों के अधिकार को)
- अनुच्छेद-19 को 'भारतीय संविधान की आत्मा'
   किसने कहा- पंडित जवाहर लाल नेहरू ने
- प्रस्तावना को 'भारतीय राजनीति की जन्मकुण्डली'
   कहा गया के. एम. मुंशी द्वारा
- मिविधान को 'एक पवित्र दस्तावेज' किसने कहा है - बी. आर. अम्बेडकर ने
- पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित
   की गई 26 जुलाई, 1947 को
- भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी - 13
- प्रारूप समिति (29 अगस्त, 1947 को गठित)
   के अध्यक्ष थे डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर
- प्रारूप सिमिति में सदस्यों की कुल संख्या 7
- ♦ संविधान के प्रारूप पर बहस हुए- 114 दिन
- संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया – जवाहर लाल नेहरू ने
- सिंवधान सभा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ - पूर्वी बंगाल से (विभाजन बाद बंबई प्रेसीडेंसी के पूर्ण से)
- स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम कानून मंत्री थे
   डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर (अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे-जोगेन्द्र नाथ मंडल)
- स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे
   आर. के, षणमुखम चेदटी

- 'झंडा समिति', 'संचालन समिति' तथा 'नियम समिति' के अध्यक्ष थे - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- 'संघ साँविधान समिति' के अध्यक्ष थे
- पं. जवाहर लाल नेहरू (कुल सदस्य-15)
   प्रांतीय सर्विधान समिति एवं सलाहकार समिति
- प्रातीय सीवधान सामात एवं सलाहकार सोमित के अध्यक्ष थे - सरदार बल्लभ भाई पटेल
- मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे - सरदार चल्लभभाई पटेल
- मूल/मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष
   थे जे. बी. कृपलानी
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था - 18 जुलाई 1947 को
- सोंविधान समा द्वारा राष्ट्रध्वज 'तिरंगा' को अपनाया गया - 22 जुलाई, 1947 को
- झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को
- भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है
   2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन
- सिवधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 11
   (कुल अवधि-165 दिन)
- संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया/अंगीकृत/अधिनियमित किया गया –
   26 नवम्बर, 1949 को
- संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता
   है 26 नवम्बर को
- सोंवधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी
   24 जनवरी, 1950 को
- संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 'जन गण मन' को स्वीकार किया गया - 24 जनवरी, 1950 को
- सॉवधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में 'वंदे मातरम्' को स्वीकार किया गया – 26 जनवरी, 1950 को
- 🔶 संपूर्ण संविधान लागू 26 जनवरी, 1950
- मूल सर्विधान लिखा गया था अंग्रेजी में
- भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक
   थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
- भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है - नंद लाल बोस ने
- संविधान का नामकरण 'भारत के संविधान'
   के रूप में किया गया है अनुच्छेद-393 में
- ∳ 'भारतीय संविधान का जनक' कहा जाता है
   डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर को
- डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म हुआ था
   14 अप्रैल, 1891 को महू, म. प्रदेश में
- भारतीय संविधान की प्रकृति है
  - एकात्मक एवं संघात्मक
- 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है' इसका तात्पर्य है - सभी धर्मों का महत्त्व स्वीकार करना
- 'भारत एक गणतंत्र है' अर्थ है भारत में राष्ट्र
   का प्रधान (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है
- भारत का संविधान है
  - अंशतः कठोर और अंशतः लचीला
- भारतीय संविधान को 'अर्द्धसंघीय संविधान'
   कहा है के. सी. व्हीयर ने

- मूल सर्विधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों
   की संख्या थी क्रमशः 395, 8, 22
- वर्तमान में अनुच्छेद है 495 से अधिक
- वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12
- वर्तमान में संविधान में कुल भाग है 25
- राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्रों
   का ब्योरा देती है पहली अनुसूची
- आठवीं अनुसूची संबंधित है भाषा से
- वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है - 22 (शुरू में थी - 14)
- सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया
   21वाँ संविधान संशोधन 1967 द्वारा
- मिणपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया - 71वाँ संविधान संशोधन 1992 द्वारा
- 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया - 92वाँ संविधान संशोधन 2003 के तहत
- हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया - 14 सितम्बर, 1949 को
- ♦ हिन्दी दिवस मनाया जाता है −14 सितम्बर को
- संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी है- भाग-17 के अनुच्छेद-343 के अनुसार
- प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में
- राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे
   वी॰ जी॰ खेर
- दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से
- केन्द्र-राज्य संबंध वर्णित है -7वीं अनुसूची में
- 7वीं अनुसूची संबंधित है केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बँटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से
- ♦ 10वीं अनुसूची संबंधित है
   दल-बदल से संबंधित प्रावधान से
- दल-बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ
   था 15 फरवरी, 1985 को
- दल-बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई
   थी 52वाँ संशोधन (1985) द्वारा
- सिवधान में देश का नाम- भारत अथवा इंडिया
- स्विधान का सबसे बड़ा भाग है 5वाँ
- संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है
- भाग-5 के अध्याय 4 में
   भाविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है - क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध
- प्रथम लिखित सॅविधान दिया अमेरिका ने
- सबसे बड़ा लिखित संविधान है- भारत का
- अनुच्छेद-1 में भारत को कहा गया है
   राज्यों का एक संघ
- नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है - अनुच्छेद-2 में
- अनुच्छेद-3 के तहत नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है - संसद को
- 🗣 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना -1953 में

- राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे
   फजल अली
- भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है –
   आंध्र प्रदेश (गठन-1 अक्टूबर, 1953 को)
- भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था - 1956 में
- असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में
- सिक्किम को 22वाँ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
   36वाँ संविधान संशोधन, 1975 द्वारा
- नागालैंड राज्य बना था
  - 13वाँ संविधान संशोधन,1962 द्वारा
- गोवा (25वाँ) पूर्ण राज्य बना था
   56वाँ संशोधन, 1987 द्वारा
- ♦ दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था
   69वाँ संशोधन, 1991 द्वारा
- छतीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना-क्रमश: 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 को
- तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2 जून,
   2014 को (आंध्र प्रदेश को विभाजित कर)
- वर्तमान में भारत में कितने राज्य है 28
- वर्तमान में भारत में केन्द्रशासित प्रदेश है- 8
- स्विधान की संप्रभुता निहित है जनता में
- संविधान में संघीय व्यवस्था (प्रशासनिक ढाँचा का मॉडल) लिया गया है - कनाडा से
- मूल कर्तव्य लिया गया है- सोवियत संघ से
- संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं
   विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया -ब्रिटेन से
- मूल/मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है - अमेरिका के संविधान से
- भारतीय सिंवधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है - जापान से
- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है- आयरलैंड से
- भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है- जर्मनी के बीमर संविधान से
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रमावित है - दक्षिण अफ्रीका
- संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है- अनु,-368 (भाग-20)
- ♦ संविधान में प्रथम संशोधन हुआ -1951 में
- सोंवधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है - किसी भी सदन में
- वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती-सूची में विषयों की संख्या है - 61, 100 और 52
- समवर्ती-सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है - केन्द्र व राज्य दोनों को
- वन एवं पर्यावरण विषय है- समवर्ती-सूची का
- समवर्ती सूची विषय लिया गया-आस्ट्रेलिया से
   शिक्षा, समाचार-पत्र विषय है समवर्ती-सूची
- 'शिक्षा' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया - 42वाँ संविधान
- संशोधन 1976 द्वारा ▶ पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून-व्यवस्था विषय है - राज्य-सूची का

- रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है - संघ-सूची का
- भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल
- ◆ एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से
- ♦ नागरिकता विषय है संघ सूची का
   ♦ नागरिकता का उल्लेख है संविधान के
- भाग-2 के अंतर्गत (अनुच्छेद 5-11 तक)

  ♦ भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है
   जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से,
- देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा ◆ पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा - 5 वर्ष तक
- देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा - 5 वर्ष तक
- पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था - 1955 में
- भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है - 6 बार ( अंतिम बार-2019 )
- नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था
   अरस्तु ने
- मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है- भाग-3 में (अनुच्छेद 12-35)
- भारत का मैग्नाकार्टा (अधिकार-पत्र) कहा
   गया है भाग-3 को
- मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7
- वर्तमान में मौलिक अधिकार है
- संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार (अनु॰-300 'क') किया गया-44वाँ संशोधन 1978 द्वारा
- मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का
   अधिकार है संसद को
- संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया - केशवानंद भारती वाद ने
- मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है -सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को
- मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है
   राष्ट्रपति
   अनुच्छेद-14 में कानून की समानता का अधिकार
- लिया गया है ब्रिटेन से
- 'अस्पृश्यता का अंत' है अनुच्छेद-17 में
- ∳ 'डपाधियों का अंत' है अनुच्छेद-18 में
- अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में
   'प्रेस की स्वतंत्रता' या 'बोलने की स्वतंत्रता'
- वर्णित है अनुच्छेद-19 (1) (क) में ♦ 'चौथा स्तंभ' इंगित करता है - प्रेस को
- ⁴ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है - अनुच्छेद-21 में
- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लिखित है - अनुच्छेद-29 में
- 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है -86वाँ संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद -21 (क) में
- ♦ 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' लागू हुआ - 1 अप्रैल, 2010 से

- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है- अनुच्छेद-24 में
- संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया - 1 अप्रैल 2010 को
- मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु
   अनुच्छेद-32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने
   प्रकार के रिट (आदेश) जारी करता है 5
- उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी
   िक्तया जाने वाला पाँच रिट है बंदी
   प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण
   तथा अधिकार पुच्छा
- ♦ उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है - परमादेश
- बंदी को 24 घंटे के अन्दर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है
   बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका
   है हैवियस कॉपर्स (बंदी प्रत्यक्षीकरण)
- किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है - अधिकार पृच्छा
- मूल अधिकारों के निलंबन (केवल आपातकालीन स्थिति में) संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है - अनुच्छेद 358 तथा 359 में
- 'नीति-निदेशक सिद्धांत' संविधान में वर्णित है
   भाग-4 में (अनुच्छेद 36-51 तक)
- 'नीति-निदेशक सिद्धांत' नहीं है वाद योग्य
- 'राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है' कहा था - के. टी. शाह ने
- ग्रन्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देशय
   है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
- मूल कर्त्तव्य वर्णित है- संविधान के भाग-4
   (क) में अनुच्छेद-51 (क) के तहत
- मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है
   पूर्व सोवियत संघ से
- भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया - 42वाँ संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर
- वर्तमान में मूल कर्त्तव्यों की संख्या है 11
- भारतीय संसद के तीन अंग है
   राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा
- संसद का स्थायी एवं उच्च सदन, जो कभी भंग नहीं होती है - राज्यसभा
- संसद का निम्न सदन कहलाता है- लोकसभा
- संसद भवन का डिजाईन तैयार किया था
   सर हर्बट बेकर और एडवर्ड लूटियंस ने
- संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में
- संसद भवन का उदघाटन किया गया था
   18 जनवरी, 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा
- सिंवधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है- अनु॰-108 के तहत
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है- साधारण विधेयक एवं विक्तः विधेयक के मामले में

- संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है- राष्ट्रपति
- संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
   करता है- लोकसभा अध्यक्ष
- भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी - दहेज निरोधक विधेयक पर, 6 मई 1961 को
- संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं - बहुमत के आधार पर
- संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता
   है प्रश्नकाल
- प्रश्नकाल की अविध होती है एक घंटा
- शून्य काल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद
   12 बजे से 1 बजे के बीच का समय
- शून्य काल का अर्थ है प्रश्न-उत्तर संत्र
- संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है, यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है - 60 दिन
- संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है - 6 माह तक
- संसद के दो क्रिमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयान्तराल होता है - 6 माह
- भारत का प्रथम नागरिक होता है- राष्ट्रपति
- ◆ सिंविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई
   है अंनुच्छेद-52 के तहत
- राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है - अमेरिका के संविधान से
- राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है
   ब्रिटेन के संविधान से
- कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति
- ♦ तीनों सेनाओं का सेनापित होता है- राष्ट्रपित
- राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनत्तम आयु 35 वर्ष
- राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष
- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रूपया
- राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से
- राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है - अनुच्छेद-54 में
- राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नमांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है- 50-50
- राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है 15000 रू. (1/6 वोट नहीं मिलने पर)
- राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है -महाभियोग द्वारा (अनुच्छेद-61 के तहत)
- च राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है - संसद के किसी भी सदन द्वारा
- राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है - 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही
- प्रष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है -उपराष्ट्रपति को

- संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है - केन्द्रीय मंत्रिमंडल
- राष्ट्रपित लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद-85 के तहत
- मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है
   राष्ट्रपति को (अनुच्छेद-72 के तहत)
- लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनित करता है - 2 (एंग्लो इंडियन)
- राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है
   प्रधानमंत्री के परामर्श से
- किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगने का अधिकार है - राष्ट्रपति को (अनुच्छेद-143 के तहत)
- भारत के प्रथम राष्ट्रपति- डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद
- प्रथम दलित राष्ट्रपति के. आर. नारायणन
- प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरि
- निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति-एन. संजीव रेड्डी
- राष्ट्रपित का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी - कैप्टन लक्ष्मी सहगल
- राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई
   फकरूद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन
- एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया - एम॰ हिदायतुल्लाह
- देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति -प्रतिभा पाटिल
- पद से त्याग-पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे
   वी.वी. गिरि
- जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपित
   भ्रे ज्ञानी जैल सिंह (भारतीय डाक
   विधेयक 1986 के संबंध में)
- दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है - राष्ट्रपति (अनुच्छेद-123 के तहत)
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है - संचित निधि द्वारा
- सिंवधान के भाग-18 में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है - राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात
- अनुच्छेद-352 संबंधित है- राष्ट्रीय आपात से
- राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह
- ◆ पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया
   26 अक्टूबर 1962 को (भारत-चीन युद्ध के समय)
- दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया
   3 दिसम्बर, 1971 को (भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय)
- आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय
   आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को
- आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है 1 माह
- अनुच्छेद-356 संबंधित है -राष्ट्रपति शासन से
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है
   राष्ट्रपति, राज्यपाल के सलाह पर ( राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर )

- सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु॰-356 के तहत)
   लागू हुआ था पंजाब में (1951 में)
- सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है
   उत्तर प्रदेश में
- सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया - पंजाब में (सबसे कम-कर्नाटक में)
- राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अविधि है -क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष
- वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती
   है राष्ट्रपित द्वारा, अनुच्छेद-360 के तहत
- → अबतक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित
   किया जा चुका है एक बार भी नहीं
- वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है - 2 माह
- राष्ट्रपित भवन को डिजाईन किया गया था
   एडविन लुटियंस द्वारा
- राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर
- सर्विधान के किस अनुच्छेद के तहत 'भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा' - अनुच्छेद-63
- राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है - उपराष्ट्रपति (अधिकत्तम 6 माह तक)
- यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन सम्भालेगा
   सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी
   विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय
- उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति
- ♦ उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को
- उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है -राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष
- ◆ उपराष्ट्रपित हेतु न्यूनत्तम आयु सीमा- 35 वर्ष
- उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन- 4 लाख रूपया
   प्रथम उपराष्ट्रपति थे- डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन
- ◆ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है
   अनुच्छेद-74 के तहत
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है
   राष्ट्रपति, अनुच्छेद-75 के तहत
- प्रथम प्रधानमंत्री थे- पं॰ जवाहर लाल नेहरू
- प्रथम उप-प्रधानमंत्री थे- बल्लभ भाई पटेल
- उप-प्रधानमंत्री पद है- पूर्णतः गैर-संवैधानिक
- प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनत्तम आयु-25 वर्ष
- प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष
- मॉत्रमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है - प्रधानमंत्री
- संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है - अनुच्छेद-352 के खंड-3 में
- मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री
- मॅत्रिपरिषद् में शामिल होते है
   प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री
- मॉिंत्रपरिषद् में मंत्री होते हैं तीन स्तर के (कैंबिनेट ', राज्य मंत्री, उपमंत्री)

- मॅत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते है
   लोकसभा के प्रति
- मॅत्रिपरिषद् का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है - प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है- अनुच्छेद 78 के तहत
- अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जानेवाले प्रथम प्रधानमंत्री - विश्वनाथ प्रताप सिंह
- प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री- मोरारजी देसाई
- प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे -अटल बिहारी बाजपेबी
- प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे- पी॰ वी॰ नरसिंहाराव
- एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले
   प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह
- 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया -द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने
- केंद्रीय मॅत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले
   व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी
- देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
- सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे- अटल बिहारी वाजपेयी (.13 दिन)
- भारत में नई संसदीय सिमिति प्रणाली की शुरूआत हुई - 1991 ई. में
- प्राक्कलन समिति में सदस्यों (कार्यकाल-1 वर्ष) की कुल संख्या - 30 (लोकसभा से)
- राज्यसमा का कोई सदस्य नहीं होता है
   प्राक्कलन समिति में
- लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या
   22 (15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से)
- प्राक्कलन समिति की जुड़वाँ बहन कहा जाता है - लोक लेखा समिति को
- लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनित या नियुक्ति करता है - लोकसभा के अध्यक्ष
- पुरानी वित्तीय समिति है− लोक लेखा समिति
- लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है - लोकसभा अध्यक्ष को
- 🛊 राज्य सभा का गठन 3 अप्रैल, 1952
- ♦ राज्य सभा की पहली बैठक- 13 मई, 1952
- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है
   एकल संक्रमणीय पद्धित द्वारा
- राज्यसभा के सदस्य चुने जाते है राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
- राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति दो वर्ष पश्चात् सेवा-निवृत हो जाते है - एक-तिहाई सदस्य
- राज्यसमा में राज्यों/संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है - उनकी जनसंख्या के अनुपात में
- राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति,
   जो राज्य सभा का सदस्य नहीं होता
- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष
- राज्यसभा में गणपूर्ति/कोरम संख्या है 1/10
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग√विघटित नहीं होता है
- राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनित करता है 12

- सदस्यों को, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से, अनुच्छेद-80 के तहत
- राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी
   बी॰ एस॰ रामादेवी
- राज्य सभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी
   - नरिगस दत्त ( अभिनेता-पृथ्वीराज कपूर )
- लोकसमा व राज्यसमा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है - क्रमश: 25 और 30 वर्ष
- लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया
   है अनुच्छेद 81 में
- ♦ लोक समा का गठन हुआ 6 मई, 1952
- लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष
- लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकत्तम सदस्य हो सकता है - क्रमणः 552 तथा 250
- वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है 545
- लोकसमा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया -31वाँ संशोधन 1973 द्वारा
- लोकसमा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है -क्रमश: 84 सीटें तथा 47 सीटें
- लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है
   जनसंख्या के आधार पर
- लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ 1952 में
- लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है - 1971 की जनगणना पर
- लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत
   राशि जब्त हो जाती है, यदि उसे प्राप्त नहीं
   होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग
- लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है
   25 हजार (एससी ∕एसटी-12500 रू.)
- लोकसमा का नेता होता है प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है
   लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा
- लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है- लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से
- लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है -उपाध्यक्ष को (उपाध्यक्ष-अध्यक्ष को)
- लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे
   जी. वी. मावलंकर
- ♦ लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे
   श्री अनंतशयनम आयंगर
- 🔷 लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष-मीरा कुमार
- ♦ लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है
   लोकसभा अध्यक्ष
- अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है
   प्रोटेम स्पीकर (नियुक्ति-राष्ट्रपति)
- प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है
- लोकसभा अध्यक्ष 'कास्टिंग वोट' प्रयोग करता है- टाई होने पर, अनुच्छेद 100 के तहत
- राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है - लोकसभा महासचिव

- किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकत्तम कितने ताराँकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं- 20
- तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है
   मौखिक रूप में
- लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते है - दो बार
- लोकसभा की अविध बढ़ाई जा सकती है
   आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए
- पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता
   दी गयी − 1969 में
- राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता
   कमलापति त्रिपाठी तथा रामसुभग सिंह
- अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है -लोकसभा में (विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रीपरिषद् के विरूद्ध)
- प्रथम स्पीकर जिनके विरूद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था - जी.
   वी. मावलंकर (प्रथम लोकसभा अध्यक्ष)
- लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है - 1/10 (अनुच्छेद-100)
- सख्या का हाता ह 1/10 ( अनुष्कद-100 )
   लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि
- किस राज्य से आते हैं उत्तर-प्रदेश से ♦ वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में
- पेश किया जाता है लोकसभा में ♦ धन विधेयक परिभाषित है- अनुच्छेद-110 में
- चन विधयक परिभाषित है अनुच्छेद-117 में
- धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है - लोकसभा में
- कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय करता है – लोकसभा अध्यक्ष
- धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है- केवल 14 दिनों तक
- धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमित लेना आवश्यक है - राष्ट्रपित की
- अनुमात लना आवश्यक ह राष्ट्रपति की • क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा
- क्षेत्र है लद्दाख (छोटा-चाँदनी चाँक)

   भारत का प्रथम/सर्वोच्च विधि अधिकारी होता
- है महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) • महान्यायवादी की नियुक्ति करता है- राष्ट्रपति
- (अनुच्छेद-76 के तहत) ♦ किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के
- बैठक में भाग ले सकता है- महान्यायवादी

  अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन
- में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल ◆ भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है
- एक कानूनी/न्यायिक सलाहकार
   राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार
- राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है - महाधिवक्ता (अनु,-165 में)
- महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की नियुक्ति करता है - राज्यपाल
- भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है - नियंत्रक य महालेखा परीक्षक को
- देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है
  - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता
   है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 (1) के तहत
- नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता
   है- नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष
- नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है - राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर, अनुच्छेद 151 के तहत
- लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक होता है - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है - भाग-5 के अनुच्छेद-124 में
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन
   किया गया था 28 जनवरी 1950 को
- सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है - अनुच्छेद-137
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश है - 34 (1 मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश)
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या
   में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति
- ♦ मुख्य न्यायाधीश का वेतन- 2,80,000 रू.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते है - राष्ट्रपति को संबोधित कर
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते है - संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
- सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधिशों को शपथ
   दिलाता है- सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिशों की सेवानिवृति की आयु है - 65 वर्ष
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
   धे हीरालाल जे॰ कानिया
- सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है - अनु॰-137 के तहत
- ★ सिवधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक
- माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को

   सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
- निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा

  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अबतक के सबसे
  बड़ी खंडपीठ (13 न्यायाधीश) का गठन
  किया गया था केशवानंद भारती केस में
- सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा
   करता है अनुच्छेद-32 के तहत
- जनिहत याचिका प्रस्तुत की जा सकती है -उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में
- पी. आई. एल (जनहित याचिका) का पूर्ण रूप है - पब्लिक इंटरेस्ट लेटिगेशन
- सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन-1862 में (कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में)
- वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25
   प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था
- की गई है अनुच्छेद 214 के तहत ♦ उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है -राष्ट्रपति (त्यागपत्र-राष्ट्रपति को)

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु है - 62 वर्ष
- ♦ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है - राज्य के संचित निधि से
- िकन दो केन्द्रशासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है - दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर
- इलाहाबाद उ. न्यायालय की स्थापना-1866 में
- दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में
- पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में
- मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है - 25 मार्च, 2013
- त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है
   26 मार्च, 2013
- पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है – चंडीगढ़
- कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है
   अण्डमान निकोबार द्वीप समृह
- मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी
- केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप
- बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र,
   गोवा, दमन-दीव तथा दादर और नगर हवेली
- िकस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है - गौहाटी उच्च न्यायालय
- किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है - इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है
   गौहाटी उच्च न्यायालय
- सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है - अंग्रेजी
- राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है - राज्यपाल
- राज्य की शक्ति निहित होती है- राज्यपाल में
- प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है -अनु॰-153 के तहत (नियुक्ति-राष्ट्रपति)
- राज्यपाल (गवर्नर) को शपथ ग्रहण करवाता
   है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- राज्यपाल पद के लिए न्यूनत्तम आयु 35 वर्ष
- ◆ राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रू.
   ◆ राज्यपाल उत्तरदायी होता है
  - राष्ट्रपति के प्रति
- भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी
   श्रीमित सरोजनी नायडू (उत्तर प्रदेश)
- राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद्, विधानसभा और राज्यपाल
- विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा
  - राज्य विधानमंडल का स्थायी/उच्च सदन कहलाता है – विधान परिषद् (अनु.-171)
- विधान परिषद् तथा विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है - क्रमश: 6 व 5 वर्ष
- राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती
   देने का अधिकार है विधान सभा को
- राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय करता है -विधानसभा अध्यक्ष

- विधान परिषद् धन विधेयक को रोक सकती है - 14 दिनों तक
- विधान परिषद् की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है - संसद को अनुच्छेद-169 के तहत, जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे
- विधान सभा अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र देता है
   उपाध्यक्ष को
- राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृति की आयु
   सीमा कोई निश्चित नहीं है
- गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर
   किया जाता है विधान मंडल द्वारा
- विधान सभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनित कर सकता है - केवल एक
- विधान सभा की न्यूनतम तथा अधिकत्तम सदस्य संख्या होती है- क्रमशः 60 तथा 500
- विधान परिषद् के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है - 1/6 सदस्य
- राज्य विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या होती है- अधिकतम (विधान सभा के सदस्यों की एक तिहाई) तथा कम-से-कम 40
- राज्य मॅत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है - विधानसभा के प्रति
- विधान परिषद् तथा विधान सभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा- क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष
- विधान सभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल होता है - 6 माह
- प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मण्डल की व्यवस्था की गयी है - अनु॰-170 के अन्तर्गत
- राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रधान होता है मुख्यमंत्री
   भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी
- सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश) ♦ निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है -
- भाग-15 के अनुच्छेद-324 से 329 में
- भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी
   25 जनवरी 1950 को
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6
   वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
- मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000
- मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है
   भारत की संचित निधि से
- चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था
- सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में
- राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है - निर्वाचन आयोग
- प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन
- मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई - 61वाँ संशोधन 1989 द्वारा
- ♦ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को
- चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया - 1993 के चुनाव में
- सिवधान का कौन-सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है - अनुच्छेद-326
- वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष

- भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरूआत की गई-2 अक्टूबर 1953 को
- मंचायती राज्य विषय है राज्य-सूची का
- 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से
   पंचायती राज का उल्लेख है भाग-9 में
- (अनुच्छेद-243 'क' से 243 'ण' तक) ♦ पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है
- पंचायता राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है
   राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत
- पंचायती राज प्रणाली आधारित है
  - सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर 73वाँ संविधान संशोधन (1992) संबंधित है
- पंचायती राजव्यवस्था से
   73वें संविधान संशोधन (1992) का अभिपालन
- करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश
   ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई
   है संविधान के भाग-4 में
- पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है -राज्य सरकार की (प्रत्येक पाँच वर्ष पर)
- भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजव्यवस्था की सिफारिश की थी - बलवंत राय समिति ने
- त्रि-स्तरीय प्रणाली में आते है ग्राम पंचायत,
   पंचायत समिति एवं जिला परिषद्
- ∳ पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है
   ग्राम पंचायत
- पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व
   करता है ग्राम सेवक
- ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है
   प्रशासनिक प्राधिकरण
- राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है - अनुच्छेद-40
- सर्वप्रथम पंचायती राजव्यवस्था लागू की गई अक्टूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में
- 'पंचायती राजव्यवस्था का वास्तुकार/शिल्पी'
   कहा जाता है बलवंत राय मेहता को
- द्वि-स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी -अशोक मेहता समिति ने (गठन-1977 में)
- पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को
- नगरपालिका का वर्णन है भाग-9 (क) में (अनुच्छेद-243P से 243ZG तक)
- नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया
   74वाँ संविधान संशोधन, 1992 द्वारा
- 12वीं अनुसूची संबंधित है- नगरपालिका से
- नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गयी है - 18
- नगरपालिका को जाना जाता है
  - शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से
- ★ स्थानीय स्वशासन विषय है राज्य-सूची का
   ★ स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन
- स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया
   गया सन् 1882 ई॰ में लार्ड रिपन द्वारा
- नगरनिगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी
   1687-88 में (मद्रास में)
- मुम्बई तथा कोलकाता प्रेसीडेंसी में नगर निगम स्थापित किया गया था - 1726 में

- नगरपालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष
- नगरिनगम का अध्यक्ष होता है महापौर/मेयर
- मेयर बनने हेतु न्यनूतम आयु सीमा- 30 वर्ष
- वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया
   है अनुच्छेद-280 में, प्रत्येक पाँच वर्ष पर
- प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में
- प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष- के.सी. नियोगी
- वर्तमान में वित्त आयोग (15वें) के अध्यक्ष है
   डॉ. एन. के. सिंह
- 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020-25
- केन्द्र-राज्य के मध्य वित्त/कर का निर्धारण करता है - वित्त आयोग
- राज्य वित्त आयोग है- एक संवैधानिक संस्था
- लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों (10) की नियुक्ति (6 वर्ष के लिए) करता है - राष्ट्रपति
- प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए (अनु-82)
- लघु संविधान (Mini Constitution) कहा जाता
   है- 42वाँ संविधान संशोधन (1976) को
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ -1980 में
- सर्वप्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ
   केरल में (1957 में)
- अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई- 8वाँ संशोधन (1959) द्वारा
- प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था
   15 सितम्बर, 1997 को
- भारत में अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन मई
   1990 में (अनुच्छेद 263 के अंतर्गत)
- सरकारिया आयोग का गठन जून, 1983
   को (केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु)
- जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया
   गया था अनुच्छेद-370 के तहत
- जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया गया- 11 अगस्त 2019 को, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 पारित कर
- लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14
   मार्च, 1982 को, जुनागढ़ (गुजरात) में
- सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन-गुजरात में
- भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में
   पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में
- कांका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में
- ♦ 'समान नागरिक संविधा' (Common Civil Code) लागू एक मात्र राज्य है – गोवा
- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
   किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद-44
- भ धारा-302 संबंधित है हत्या से
- धारा-307 संबंधित है- हत्या की कोशिश से
- + 'सूचना के अधिकार' अधिनियम को राष्ट्रपति
   की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून, 2005 को
- सूचना का अधिकार है विधिक अधिकार
- 'सूचना के अधिकार' की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है - अरूणा राय